पंडित शम्बू नाथ टिकू एवं अन्य

बनाम

सरदार ज्ञान सिंह एवं अन्य

30 जून, 1995

[के. रामास्वामी और एन. वेंकटाचल, न्यायमूर्तिगण]

संपत्ति कानून : संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 / उपभोगाधिकार अधिनियम, 1882 – विवादित संपत्ति – भूमि, धर्मशालाएँ, मंदिर और झरने जो अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित हैं – वाद वादियों द्वारा दायर किया गया अर्थात् हिंदुओं द्वारा – (क) प्रतिवादियों अर्थात् सिखों को वाद संपत्ति के दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित कर दिए गए) से बेदखल करने के लिए और (ख) स्थायी निषेधाज्ञा के लिए ताकि प्रतिवादियों को विवादित संपत्ति पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने तथा उक्त संपत्ति पर धार्मिक अनुष्ठानों और पूजाओं के उनके संपादन में बाधा डालने से रोका जा सके – क्या प्रतिवादी द्वारा उन दो कमरों का कब्जा अनुमतिपूर्ण था और इसलिए धर्मार्थ के उत्तराधिकारियों के रूप में वादियों द्वारा निरस्त किया जा सकता था – क्या प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उन दो कमरों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था या उन्हें स्वामित्व प्राप्त हो गया था, क्योंकि उनका कब्जा महाराजा प्रताप सिंह द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया था – क्या प्रतिवादियों को विवादित भूमि के खुले स्थानों पर धार्मिक सभाओं या देवड़ियों के उपयोग हेतु उपभोगाधिकार प्राप्त था या नहीं।

भारत का संविधान – अनुच्छेद 142 – धार्मिक सभाओं के लिए उपभोगाधिकार से संबंधित विवाद – पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग किया गया।

अपीलकर्ता, जो हिंदू हैं, ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना की गई ताकि प्रतिवादियों को (क) तिरथ मार्तंड, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित कुछ भूमि, धर्मशाला, मंदिरों और झरनों पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके; (ख) उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में बाधा डालने से; और (ग) विवादित जी भूमि पर निर्माण करने से; (घ) तथा दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों से प्रतिवादियों को बेदखल करने के लिए।

वाद आंशिक रूप से आज्ञप्ति किया गया कि प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा किसी भी प्रकार से हिंदुओं द्वारा धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से तथा मार्तंड परिसर में किसी भी गुरुद्वारे के निर्माण से रोका गया, लेकिन उक्त दो कमरों से प्रतिवादियों की बेदखली के संबंध में वाद अस्वीकार कर दिया गया, जिन्हें वे अपने पवित्र 'ग्रंथ साहिब' को आयोजित करने के लिए उपयोग कर रहे थे।

इससे आक्रोशित होकर, वादियों तथा प्रतिवादियों दोनों ने अपनी-अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में प्रथम अपीलें दायर कीं।

इस निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से वादी की अपील को इस सीमा तक स्वीकार किया कि प्रतिवादियों द्वारा खाली स्थान में दीवान आयोजित करने कि तीन निर्दिष्ट अवसरों—अर्थात बैसाखी, दशमी और छठी पादशाही—तक सीमित कर दिया, लेकिन दूसरी ओर प्रतिवादियों की अपील को संपूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

विवाद में पारित आदेश, जिसे उच्च न्यायालय में अपील में पुष्टि की गई थी, इस प्रकार वादियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दों तक सीमित चुनौती दी गई: (क) निचली अदालतों द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध

धर्मशाला के दो कमरों से बेदखली की आदेश देने से इंकार, और (ख) खाली स्थान में दीवान आयोजित करने के संबंध में प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान न करना, उनके पक्ष में उससे संबंधित उपभोगाधिकार को मान्यता देते हुए।

उक्त दो कमरों के संबंध में बेदखली के दावे के विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि (क) जम्मू राज्य के तत्कालीन शासक महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सिख समुदाय को दिए गए अनुदान के तहत वे उनके स्वामी बन गए थे; (ख) या वैकल्पिक रूप से, उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उन कमरों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था; (ग) और यह कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष तीन विशिष्ट धार्मिक अवसरों पर मारलैंड श्राइन के खुले स्थान में दीवान आयोजित करने के उपभोगाधिकार भी प्राप्त कर लिए थे, अतः उन्हें उक्त दीवान आयोजित करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका नहीं जा सकता।

वर्तमान विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचाने के सभी प्रयास विफल हो जाने पर, यह न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निर्णय करता है।

अभिनिर्धारित : 1. महाराजा प्रताप सिंह द्वारा अनुदान दिए जाने की दलील, जिसे प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में पहले प्रस्तुत नहीं किया था, विधि की दृष्टि में अस्थिर है। [712-सी]

2. दो कमरों का कब्जा, जो महाराजा प्रताप सिंह के कहने पर 'ग्रंथ साहिब' को आयोजित करने के लिए सिख समुदाय को दिया गया था, पूरी तरह से अनुमतिपूर्ण कब्जे की प्रकृति का था। अनुमतिपूर्ण कब्जा को प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो कि कब्जे में रहने वाले व्यक्ति ने वास्तविक स्वामियों के ज्ञान में संपत्ति पर प्रतिकूल अधिकार का दावा बारह वर्षों या उससे अधिक अवधि तक किया हो।

[712-एच, 713-बी]

प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में यह अवश्य कहा है कि वे न केवल कमरों के कब्जे में थे, बल्कि पूरे मंदिर और उसके परिसर के भी बारह वर्षों से

अधिक अवधि तक कब्जे में थे, किन्तु उन्होंने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने धर्मार्थ विभाग, जो मंदिर और धर्मशाला के प्रबंधन में था, उसको यह सूचित किया था कि उन्होंने उन दो कमरों के अपने अनुमत कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में परिवर्तित कर दिया है। इस वाद में यह भी कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है कि क्या प्रतिवादियों ने उक्त कमरों पर प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपना स्वामित्व सिद्ध कर लिया था या नहीं। [714-बी सी]

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम अरविंदन कुनजू पनिकर एवं अन्य, **ए आई आर (1971) सर्वोच्च न्यायालय 996, का संदर्भ दिया गया।**

3. सामान्यतः खुले स्थान का कब्जा उस भौतिक संरचना, भवनों और स्रोतों के कब्जे के साथ ही माना जाएगा, जिनके बीच वह स्थित होता है। [719-ए]

पूरा मंदिर, जिसमें खाली स्थान भी शामिल है, जैसा कि राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है, प्राचीन काल से हिंदुओं के कब्जे में रहा है। किसी अन्य की भूमि के उपयोग का अधिकार प्रथा के आधार पर तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उस अधिकार का दावा करने वाला पक्ष यह सिद्ध न कर दे कि वह अधिकार प्राचीन, शांतिपूर्ण, उचित और विशिष्ट था तथा उसे अधिकार के रूप में निरंतर बिना किसी हस्तक्षेप के प्रयोग किया जाता रहा है। [719-ई एच, 720-ए]

राजा ब्रजा सुंदर देब एवं अन्य बनाम मणि बेहरा एवं अन्य, **ए आई आर (1951) सर्वोच्च न्यायालय 247, का संदर्भ लिया गया।**

4. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खुले स्थान के संबंध में अपने स्वामित्व अधिकारों को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण, तथा अपनी लिखित बयान में वैकल्पिक दावा न किए जाने की स्थिति में, उपभोगाधिकार के आधार पर ऐसे अधिकारों के अर्जन के आधार पर दीवान आयोजित होने का उनका दावा विधि में स्थायी नहीं है। [721-डी]

5. यद्यपि प्रतिवादियों ने दो कमरों पर कोई स्वामित्व अधिकार न तो महाराजा प्रताप सिंह द्वारा दिए गए अनुदान से प्राप्त किया है और न ही प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपना अधिकार पूर्ण किया है, तथापि न्याय के हित में यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें उन दो कमरों से बेदखल किया जाए, जहाँ वे अपना 'ग्रंथ साहिब' रखते हैं। हालांकि, उन दो कमरों पर उनके कब्जे का अधिकार अनुमतिप्राप्त कब्जा माना जाएगा और सिखों द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य, जिससे विवादित संपत्ति में पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती है, वादियों को विधिक कार्यवाही का सहारा लेकर प्रतिवादियों को बेदखल करने का कारण प्रदान करेगा। [723-सी-डी]

6. यद्यपि प्रतिवादी खुले स्थान में दीवान आयोजित करने के लिए उपभोगाधिकार स्थापित करने में विफल रहे हैं, लेकिन सिखों को दो कमरों के उपयोग की अनुमति देने के बाद, न्याय के हित में उन्हें मार्तंड मंदिर के खुले स्थान में दीवान आयोजित करने से रोकना उचित नहीं होगा, जब कि आवश्यकता के कारण उन्हें उस स्थान के निकट दीवान आयोजित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जहाँ उनका पवित्र ग्रंथ रखा जाता है। अतः जब भी प्रतिवादी वर्ष में तीन अवसरों में से किसी पर दीवान आयोजित करने का निर्णय लें, तो उसे इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसमें भाग लेने वाले लोग उक्त खुले स्थान तक पहुँचें, बिना मंदिर परिसर या उन जलस्रोतों को पार किए जहाँ हिंदू अपने पूजा-अर्चना करते होंगे। (23-जी -एच, 724-ए-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 865/1973

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एल.पी.ए. संख्या 83/1967 में 3.5.72 के निर्णय और आदेश से,

डी.वी. सहगल, के.सी. दुआ, वाई.पी. महाजन, जी. जुनेजा, रतन लाल, सुश्री उषा यादव, सुश्री मोनिका गुसाईं और बिमल रॉय जद अपीलकर्ताओं की ओर से।

एम. एस. गुज्राल, वी.जे. फ्रांसिस और वी. सुब्रमणियन प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

वेंकटाचला, न्यायाधीश अपीलकर्ता वादी थे जबकि प्रतिवादी, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में सिविल मूल वाद संख्या 20/1958 में प्रतिवादी थे, जो अनंतनाग जिले में मारलैंड श्राइन के संबंध में दायर किया गया था। वाद में मांगी गई आदेश स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए थी ताकि प्रतिवादियों को वादियों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके, जो भूमि 19 कनाल 12 मरला क्षेत्रफल की है, सर्वे प्लॉट 1424/4, 1962/1424/4 और 2304/1143/1 में, जिनका माप क्रमशः (19 कनाल 6 मरला, 6 मरला) और 9 कनाल 18 मरला है, तथा धर्मशालाएं, मंदिर और तीर्थ मारलैंड में स्थित झरने, ग्राम माचा भवन, तहसील अनंतनाग; हिंदुओं को मंदिरों में देवताओं की पूजा करने या उनके धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन में बाधा डालने और विवादित भूमि पर किसी भी निर्माण को खड़ा करने से रोकने के लिए; तथा मारलैंड के झरनों के दक्षिणी भाग में स्थित धर्मशाला के छह कमरों में से दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) से प्रतिवादियों की बेदखली के लिए। विवाद में मांगी गई आदेश आंशिक रूप से इस हद तक प्रदान की गई कि प्रतिवादियों को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा किसी भी प्रकार से हिंदुओं द्वारा तीन झरनों (कमल कुंड, बिमल कुंड और गौरी कुंड) पर धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन में हस्तक्षेप करने से, या मंदिरों में पूजा करने से तथा झरनों के उत्तर दिशा में पहलगाम की ओर खुली जगह में मल मास, बन मास, सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोमवती अमावस्या (सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या), अमरनाथ जी यात्रा अवधि और विजय सप्तमी (हिंदू महीने का 7वां दिन जो रविवार को पड़ता है) के अवसरों पर दीवान आयोजित करने से, तथा धर्मशाला के उत्तर में पहलगाम रोड की ओर स्थित भवन पर वादियों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से और मारलैंड परिसर में किसी भी गुरुद्वारे के निर्माण से रोका गया। लेकिन, प्रतिवादियों को धर्मोहल्ला के उनके कब्जे वाले दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित कर दिए गए) से बेदखल करने के संबंध में तथा प्लॉट संख्या 2304/1143/1 में चार मरला भूमि के संबंध में मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा के विषय में आदेश देने से इंकार कर दिया गया।

उक्त वाद में पारित आदेश को वादियों द्वारा उसी उच्च न्यायालय में उनके द्वारा दायर प्रथम अपील संख्या 83/67 में इस सीमा तक चुनौती दी गई कि उसमें कुछ राहतें प्रदान नहीं की गई थीं, जबकि प्रतिवादियों द्वारा इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि उनके विरुद्ध कुछ राहतें प्रदान की गई थीं, जिसके लिए उन्होंने सिविल प्रथम अपील संख्या 87/67 दायर की। मियाँ जलाल-उद-दीन और अनंत सिंह, जे.टी. से गठित एक खंडपीठ ने उक्त दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुना। चूँकि उन अपीलों में पृथक-पृथक निर्णय देने वाले माननीय न्यायाधीश उनके समक्ष विचारार्थ उत्पन्न हुए दो बिंदुओं पर सहमति तक नहीं पहुँच सके, इसलिए उन्होंने माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि जिन दो बिंदुओं पर वे सहमत नहीं हो सके, उन्हें उनकी राय के लिए किसी तीसरे न्यायाधीश को संदर्भित किया जाए, और इसके लिए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

> "जैसा कि मेरे विद्वान सहोदर अनंत सिंह न्यायाधीश और मैं प्रतिकूल कब्जे से संबंधित प्रश्नों तथा प्रतिवादियों द्वारा दीवान आयोजित करने के अधिकार के संबंध में अपने-अपने निर्णयों में सहमत नहीं हो सके हैं, अतः यह मामला माननीयगण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि इन बिंदुओं को उनके माननीयगण द्वारा नामित किसी तृतीय न्यायाधीश को संदर्भित किया जा सके।"

मुफ्ती बहा-उद-दीन फारूकिक, न्यायाधीश तीसरे न्यायाधीश के रूप में, जिनके पास उक्त दो बिंदु उनके मत के लिए संदर्भित किए गए थे, अपने निर्णय में उन बिंदुओं का इस प्रकार उल्लेख करते हैं : ·

> अनंत सिंह, न्यायाधीश ने माना कि दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों पर प्रतिवादियों का कब्जा अनुमति-आधारित था और इसे वादियों द्वारा धर्मार्थ के उत्तराधिकारी के रूप में वापस लिया जा सकता था। खुले स्थान पर दीवान आयोजित करने के संबंध में उन्होंने माना कि इसका उपयोग प्रथा पर आधारित हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में जो यह दर्शाए कि दीवान हर वर्ष निर्दिष्ट अवसर

पर आयोजित किया जाता था और प्राचीन काल से अधिकार के रूप में रखते रहे थे, प्रतिवादियों के पक्ष में कोई अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण पर उन्होंने माना कि इन दो बिंदुओं पर एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को निरस्त किया जाना चाहिए।

मियां जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश, ने हालांकि विपरीत मत व्यक्त किया। उन्होंने माना कि प्रतिवादी दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों के कब्जे में अपने अधिकार से थे और वैकल्पिक रूप से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर थे। जहाँ तक खुले स्थान पर दीवानों के आयोजन का संबंध है, उन्होंने माना कि सिख पिछले पचास वर्षों से अधिक समय से, वादियों की जानकारी में और उनकी ओर से बिना किसी आपत्ति के, निर्दिष्ट अवसरों अर्थात बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही पर इसका उपयोग करते रहे हैं, और यह वादियों को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत मांगने से वंचित करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि ऐसा करना इन अवसरों पर सिखों द्वारा दीवानों के आयोजन के अधिकार के प्रतिकूल होगा।

इसलिए, फ़ारूक़ी, न्यायाधीश, तीसरे न्यायाधीश के अनुसार, अपील में वे बिंदु जिन पर अनंत सिंह, न्यायाधीश और मियां जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश सहमत नहीं हुए थे और जिन्हें उनकी राय के लिए संदर्भित किया गया था—जो प्रतिकूल कब्ज़े से संबंधित थे और जो प्रतिकूल कब्ज़े के अधिकार से संबंधित थे तथा जो प्रतिवादियों द्वारा दीवानों को आयोजित करने के अधिकार से संबंधित थे—ये थे;

1. क्या दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों पर प्रतिवादियों का कब्जा अनुमतिपूर्ण था और इसलिए धर्मार्थ के उत्तराधिकारियों के रूप में वादियों द्वारा निरस्त करने योग्य था, जैसा कि अनंत सिंह, न्यायाधीश ने माना, या दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों पर प्रतिवादियों का कब्जा उनके अपने अधिकार में था या वैकल्पिक रूप से प्रतिकूल कब्जे के रूप में था, जैसा कि मियां जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश ने माना।

2. क्या प्रतिवादियों को प्रथा के आधार पर पहलगाम की ओर उत्तर दिशा में स्थित खुले स्थान में 'दीवान' आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह दिखाने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि 'दीवान' प्रत्येक वर्ष विशिष्ट अवसरों पर और अनादिकाल से आयोजित किए जा रहे थे, जैसा कि ["अनंत सिंह","न्यायाधीश"], ने माना; अथवा क्या वादियों को प्रतिवादियों के विरुद्ध उस खुले स्थान में तीन विशिष्ट अवसरों—बैसाखी, दसवीं और छट्टी पादशाही—पर 'दीवान' आयोजित करने से स्थायी निषेधाज्ञा मांगने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसे 'दीवान' 50 वर्षों से अधिक समय से वादियों की जानकारी में और उनके किसी भी आपत्ति के बिना आयोजित किए जा रहे थे, जैसा कि मियाँ जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया।

फारूकी, न्यायाधीश, तीसरे न्यायाधीश की बिंदु-1 पर इस प्रकार राय व्यक्त की गई थी:

महाराजा प्रताप सिंह, एक संप्रभु शासक, जिन्हें धर्मशाला के साथ किसी भी प्रकार से व्यवहार करने का अधिकार था, उन्होंने धर्मशाला के दो कमरे सिखों को समर्पित कर दिए। ऐसी समर्पण को महाराजा द्वारा किसी भी समय वापस नहीं लिया गया। मात्र इस तथ्य से कि रसीद, प्रदर्श अ.स. 3/1 में पूरे धर्मशाला को धर्मार्थ द्वारा प्रोहित सभा को हस्तांतरित संपत्तियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, सिखों के पक्ष में समर्पण की कानूनी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादियों का दो कमरों के लिए दावा, जो अनुमतिपूर्ण कब्जे पर आधारित था, असत्य था। वादी कमरों के कब्जे को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते, भले ही यह मान लिया जाए कि उनके पास उस पर स्वामित्व था, क्योंकि कमरों के कब्जे के लिए वाद, बेदखली की तारीख से 12 वर्षों के भीतर दायर न किए जाने के कारण, सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रतिबंधित था। अन्यथा प्रतिवादियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि उन्होंने वाद दायर किए जाने तक प्रतिकूल कब्जे के द्वारा संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था।

फारूकी, न्यायाधीश, तीसरे न्यायाधीश की बिंदु-2 पर इस प्रकार राय व्यक्त की गई थी:

प्रतिवादियों ने यह दिखाया था कि सिखों को खाली स्थान पर धार्मिक सभा के लिए उपयोग करने हेतु उपभोगाधिकार तीन विशेष अवसरों—बैसाखी, दसवीं और छठी पातशाही—पर प्राप्त था, और इस प्रकार प्रतिवादियों का उस स्थान का उपयोग दीवान आयोजित करने के लिए केवल उन्हीं तीन अवसरों तक सीमित होना चाहिए।

अपीलों में दिए गए उनके पृथक निर्णयों में दो न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर व्यक्त सहमति मत, तथा इस निर्णय में उक्त दो बिंदुओं पर, जो उनके मत के लिए संदर्भित किए गए थे, तीसरे न्यायाधीश द्वारा व्यक्त मत ने न केवल वादियों की प्रथम अपील को खारिज करने की ओर अग्रसर किया, सिवाय इसके कि खाली स्थान में प्रतिवादियों द्वारा दीवान आयोजित करने को तीन निर्दिष्ट अवसरों—बैसाखी, दसवीं और छठी पातशाही—तक सीमित रखा जाए, बल्कि प्रतिवादियों की प्रथम अपील को भी पूर्ण रूप से खारिज कर दिया।

उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर प्रथम अपीलों में, जिसमें वादियों की प्रथम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और प्रतिवादियों की प्रथम अपील को पूर्णतः खारिज कर दिया गया, यद्यपि वादियों ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है, प्रतिवादियों ने ऐसी कोई अपील दायर करना उचित नहीं समझा। दूसरे शब्दों में, वाद में पारित तथा अपीलों में पुष्टि की गई आदेश, जो अब तक अप्रश्नित है, वह प्रतिवादियों के विरुद्ध पारित वह आदेश है, जिसमें उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका गया है कि वे किसी भी प्रकार से हिंदुओं द्वारा तीन कुंडों {कमल कुंड, बिमल कुंड और गौरी कुंड} में धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में, जो दो कनाल क्षेत्र में स्थित हैं, या कुंडों के अत्यंत पश्चिम में स्थित तीन मंदिरों में से एक, जिसे सुताज मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंदुओं द्वारा पूजा करने

में, या प्लॉट संख्या 1424/4 में एक कनाल पाँच मरला में स्थित धर्मशाला भवन के छह कमरों में से चार कमरों के कब्जे और उपयोग में, तथा स्नानगृहों के कब्जे और उपयोग में, और पाठशाला प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन के कब्जे और उपयोग में, तथा कुंडों के उत्तर में पहलगाम रोड की ओर स्थित खुले स्थान, जो 16 कनाल और 6 मरला क्षेत्र को आच्छादित करता है, के कब्जे और उपयोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, सिवाय उन अवसरों के जब प्रतिवादी बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही के अवसरों पर दीवानों के लिए उसका उपयोग करते हैं; यह सब श्री मार्तंड तीर्थ, ग्राम माचा भवन, तहसील अनंतनाग से संबंधित है।

अतः, इस न्यायालय के समक्ष वादियों द्वारा दायर वर्तमान अपील में चुनौती के अधीन, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपीलों में पुष्टि की गई वाद की आदेश निम्नलिखित तक सीमित है।

(1) छह कमरों वाली धर्मशाला में से दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में बदल दिया गया है) से, जो प्लॉट संख्या 1424/4 में एक कनाल पाँच मरला भूमि पर स्थित हैं, प्रतिवादियों को बेदखल करने का निर्देश देने से इंकार करना, यह मानते हुए कि प्रतिवादियों ने उस पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, चाहे वह महाराज प्रताप सिंह द्वारा अनुदान के रूप में दिए गए कब्जे के कारण हो या प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के कारण; और

(2) प्रतिवादियों को बैसाखी, दसवीं और छट्टी पादशाही के विशेष अवसरों पर पहलगाम की ओर झरनों के उत्तर में खुले स्थान पर दीवान आयोजित करने से रोकने से इंकार करना, उनके ऐसे दीवान आयोजित करने के उपभोगाधिकार को मान्यता देते हुए।

अतः, इस अपील में वादी-अपीलकर्ताओं द्वारा जिस बात पर प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि निचली अदालतों द्वारा उनके मुकदमे में प्रतिवादियों के विरुद्ध धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) से उनके निष्कासन के लिए आदेश देने से इनकार किया गया, तथा बैसाखी,

दसवीं और छट्टी पादशाही के तीन अवसरों पर पहलगाम की ओर खुले स्थान में दीवान आयोजित करने के संबंध में प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा न देने से, उनके उस पर उपभोगाधिकार को मान्यता नहीं दी गई।

इससे पहले कि हम वर्तमान अपील में वादियों की ओर से उठाए गए प्रश्नों पर विचार करें, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का हमारा प्रयास सफल नहीं हो सका।

वादी ने अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया कि वे धर्मशाला में स्थित उन दो कमरों (जो अब तीन कमरों में परिवर्तित हो चुके हैं), जो प्रतिवादियों के कब्जे में थे, पर अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार हैं, यदि प्रतिवादी यह आश्वासन दें कि वे बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही के तीन अवसरों पर अपने दीवान आयोजित करने के लिए पहलगाम रोड से सीधे पहलगाम की ओर से खुले स्थान में प्रवेश करेंगे और उस खुले स्थान में प्रवेश के लिए मार्तंड तीर्थ के परिसर, जहाँ झरने स्थित हैं, से होकर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन वादी ने इस बात से सहमति नहीं दी कि प्रतिवादी पहलगाम रोड से सीधे उक्त खुले स्थान में प्रवेश करके वहाँ दीवान रखे, यह कहते हुए कि धर्मशाला के वे दो कमरे (अब तीन कमरों में परिवर्तित) तीर्थ और झरनों की ओर खुलते हैं, और इसलिए उन्हें मार्तंड तीर्थ के परिसर को पार करके खुले स्थान में दीवान आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चूँकि धर्मशाला के कमरों के तीर्थ की ओर खुलने के संबंध में प्रतिवादियों का दावा वादीगण द्वारा विवादित किया गया था, हमने एक आयुक्त नियुक्त किया ताकि वह स्थानीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तथापि, जैसा कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा हमें बताया गया कि स्थल पर जो वातावरण था वह आयुक्त के लिए स्थानीय निरीक्षण करने हेतु सुरक्षित नहीं था और पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए हमारे पास अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनकर उसका निर्णय करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

अतः, हमने अपील में प्रतिस्पर्धी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों का

सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है और इस निर्णय के माध्यम से गुण-दोष के आधार पर अपील का निर्णय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

वे बिंदु जिन पर विचार करना और उत्तर देना आवश्यक है ताकि वादियों की अपीलों का निर्णय किया जा सके, उक्त मौखिक तर्कों और प्रतिस्पर्धी पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की लिखित प्रस्तुतियों के आलोक में, उचित और प्रभावी विचार हेतु इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं, इस प्रकार अतः,

1. क्या यह निष्कर्ष कि वाद में प्रतिवादी ने मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) के संबंध में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा, जब वे जम्मू राज्य के संप्रभु शासक थे, दिए गए एक 'विशिष्ट अनुदान' के कारण स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, जिसे उच्च न्यायालय के माननीय तृतीय न्यायाधीश (फारूकी, न्यायाधीश) द्वारा दर्ज किया गया, जिनके निर्णय के लिए दो प्रश्न—एक प्रतिकूल कब्जे से संबंधित और दूसरा दीवानों के धारण से संबंधित—जिन पर अपीलों का निर्णय करने वाली खंडपीठ के दो न्यायाधीश सहमत नहीं थे, क्या अस्थिर है?
2. क्या मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) का कब्जा, जो वर्ष 1913 ई. में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सिख समुदाय (जिसका प्रतिनिधित्व अब प्रतिवादी कर रहे हैं) को दिया गया था, केवल अनुमति-आधारित कब्जे की प्रकृति का था, जैसा कि वादियों द्वारा दावा किया गया है? विद्वान अधिवक्ताओं की लिखित प्रस्तुतियों के आलोक में, उचित और प्रभावी विचार हेतु इस प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं?
3. क्या उच्च न्यायालय के माननीय तृतीय न्यायाधीश (फ़ारूक़ी, न्यायाधीश) का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादियों ने मार्तंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के छह कमरों में से दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) पर प्रतिकूल कब्ज़े द्वारा स्वामित्व प्राप्त कर लिया था—जिस निर्णय के लिए अपील में उत्पन्न ऐसे प्रतिकूल कब्ज़े से संबंधित प्रश्न उन्हें संदर्भित किया गया था—अस्थिर है?

4. क्या उच्च न्यायालय के माननीय तृतीय न्यायाधीश (फ़ारूक़ी, न्यायाधीश) का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादियों ने पहलगाम रोड की ओर स्थित मार्तंड श्राइन के खुले स्थान में तीन अवसरों—बैसाखी, दशवीं और छट्टी पादशाही—पर अपने दीवान आयोजित करने का उपभोगाधिकार प्राप्त कर लिया था—जिस निर्णय के लिए अपील में ऐसे दीवान आयोजित करने से संबंधित प्रश्न उन्हें संदर्भित किया गया था— अस्थिर है?
5. यदि यह पाया जाता है कि प्रतिवादी (सिख) दक्षिणी धर्मशाला ऑफ मारलैंड श्राइन के छह कमरों में से दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) के संबंध में या तो महाराजा प्रताप सिंह द्वारा दिए गए अनुदान के कारण या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर शीर्षक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो क्या प्रतिवादी के उन दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) से बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। दक्षिणी धर्मशाला से, जब परिवर्तित कमरों में से दो का उपयोग उनके पवित्र 'ग्रंथ साहिब' को आयोजित करने के लिए किया जाता है और एक परिवर्तित कमरे का उपयोग गरीबों को भोजन खिलाने के लिए भोजन तैयार करने हेतु रसोई या लंगर कक्ष के रूप में किया जाता है, या क्या प्रतिवादियों को उचित प्रतिबंधों के अधीन अनुमेय कब्जे में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है ?
6. यदि यह पाया जाता है कि प्रतिवादियों (सिखों) ने हर वर्ष बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही के तीन अवसरों पर पहलगाम रोड की ओर स्थित मारलैंड और श्राइन के खुले स्थान में दीवान आयोजित करने का उपभोगाधिकार प्राप्त नहीं किया था, तो क्या प्रतिवादी उस खुले स्थान में उक्त दीवान आयोजित करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने के लिए उत्तरदायी हैं, या प्रतिवादियों (सिखों) को उस खुले स्थान में ऐसे दीवान आयोजित करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उसके उपयोग पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जाएँ?

उक्त बिंदुओं को अब क्रमवार विचार हेतु लिया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा

बिंदु-1:

यह बिंदु सिख समुदाय—प्रतिवादियों—द्वारा मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) पर अनुदान के अंतर्गत स्वामित्व प्राप्ति के निष्कर्ष की स्थिरता से संबंधित है, जैसा कि फ़ारूकी, न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किया गया है।

वादियों का मामला, जिसमें उन्होंने मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं) से प्रतिवादियों को बेदखल करने की मांग की है, जैसा कि उनके वाद-पत्र के अनुच्छेद 2, 4, 5, 10, 12 और 14 में प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार है :

"2. कि वहाँ एक तीर्थ है जिसका नाम मार्तंड तीर्थ है, जो ग्राम माचा भवन, तहसील अनंतनाग में स्थित है, और यह प्राचीन काल से हिंदुओं का अस्तित्व में है।

3. ....

4. कि हिंदुओं के कब्जे का विधिवत रूप से राजस्व अभिलेख और सेटलमेंट रिकॉर्ड में प्राचीन समय से दर्ज है और यह हिंदुओं के कब्जे में तथा उनके स्वामित्व के अंतर्गत है,
हिंदू, ...

5. कि जब से धर्मशाला विभाग अस्तित्व में आया है, यह धर्मशालाओं और मंदिर की देखरेख, प्रबंधन और संरक्षण कर रहा है

6. ....

7. ....

8. ....

9. ....

10. कि धर्मार्थ विभाग ने सिखों को अस्थायी रूप से दो कमरों में ग्रंथ साहिब आयोजित करने की अनुमति दी थी, जब उनकी धर्मशाला, जो

मारलैंड तीर्थ से बहुत दूर स्थित थी, ध्वस्त हो गई थी और उन्हें यह अनुमति अस्थायी रूप से दी गई थी ताकि धर्मशाला के पुनर्निर्माण तक वे वहाँ ग्रंथ साहिब रख सकें। सिखों ने अपना स्वयं का गुरुद्वारा बनाने से परहेज किया और धर्मार्थ विभाग ने प्रतिवादियों पर उक्त कमरों को खाली करने का दबाव डाला। इसके परिणामस्वरूप सिखों और धर्मार्थ विभाग के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और उसने गंभीर रूप धारण कर लिया। इस विवाद के कारण सरकार ने हस्तक्षेप किया और जम्मू-कश्मीर सरकार के हस्तक्षेप पर सिखों ने सरदार कन्या सिंह, सरदार गुलाब सिंह, सरदार निर्मल सिंह और डॉ. जसवंत सिंह को अपने प्रतिनिधि और अधिवक्ता के रूप में नामित किया और धर्मार्थ विभाग तथा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री के साथ यह निर्णय लिया गया कि दोनों कमरे खाली कराए जाएंगे और ग्रंथ साहिब को नई धर्मशाला में रखा जाएगा और ये दोनों कमरे अस्थायी रूप से ग्रंथ साहिब के लिए उपयोग किए जाएंगे, जब तक कि नई धर्मशाला का निर्माण सरकारी खर्च पर नहीं हो जाता। यह समझौता विलेख 4 असूज, 1992 को उपरोक्त प्रतिनिधियों और धर्मार्थ विभाग द्वारा, उस समय के वज़ीर वज़ारत अनंतनाग और माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया, जिसके द्वारा धर्मार्थ विभाग और प्रतिवादियों (सिखों) के बीच का विवाद समाप्त हो गया। जिस समय दिनांक 4 असूज 1992 का विलेख निष्पादित किया गया, उस समय सिखों ने इन दो कमरों को चार कमरों में परिवर्तित कर दिया था और वर्तमान में इन चार कमरों को फिर से दो कमरों और एक रसोई में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. ....

12. यह कि वादी इस तीर्थ के पीढ़ी दर पीढ़ी पुराने पुरोहित रहे हैं। धर्मार्थ विभाग के अस्तित्व में आने से पहले इस तीर्थ का प्रबंधन वादियों के बुजुर्गों के पास था। धर्मार्थ विभाग ने महाराजाधिराज के आदेश से 22 सावन 2007 को प्रबंधन छोड़कर इसे वादियों को सौंप

दिया और इसका प्रबंधन धर्मार्थ विभाग के स्थान पर वादियों को दे दिया, जैसा कि पूर्व में प्राचीन समय में था। मामले के निपटारे को सुगम बनाने के लिए धर्मार्थ परिषद को औपचारिक प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। वादी प्रतिवादियों से इन कमरों को खाली करने और वर्तमान कमरों से ग्रंथ साहिब को निकालकर अन्य व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रतिवादी टालमटोल करते रहे। वादियों के बार-बार आग्रह करने पर प्रतिवादियों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया और इन कमरों पर जबरन कब्जा करने के लिए अत्याचार करने लगे तथा खंजर निकालकर वादियों को डराया-धमकाया, झरनों पर कब्जा करने का प्रयास किया और हिंदुओं को उनके धार्मिक अनुष्ठान करने में बाधा डालने की कोशिश की तथा यह दिखाने का प्रयास किया कि यह तीर्थ गुरु नानक जी का है। वे लगभग दो वर्षों तक समय-समय पर उपद्रव करते रहे। धीरे-धीरे यह उपद्रव बढ़ता गया, यहां तक कि सरकार ने स्वयं इस पवित्र मारलैंड तीर्थ का कब्जा अपने हाथ में ले लिया और पुलिस पहरा तैनात कर दिया, ...

13. ....

14. यह कि वे दो कमरे अस्थायी आधार पर प्रतिवादियों के कब्जे में हैं, जो वर्तमान में तीन कमरों के रूप में मौजूद हैं। वादी इन कमरों के कब्जे के हकदार हैं और प्रतिवादी इन कमरों से ग्रंथ साहिब को हटाने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि वर्ष 1992 में प्रतिवादियों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया गया और सहमति दी गई थी। जम्मू और कश्मीर सरकार तथा धर्मार्थ विभाग, जो मारलैंड तीर्थ का प्रबंधन निकाय था, ने सहमति दी थी कि कुछ समय के लिए ग्रंथ साहिब को आयोजित करने की अनुमति दी जाए और ग्रंथ साहिब को कहीं और रखा जाए, जो प्रतिवादियों ने नहीं किया। इसलिए, वादी इन कमरों से उन्हें बेदखल कराने के इच्छुक हैं और कब्जे के हकदार हैं ...."

प्रतिवादियों द्वारा दायर किए गए दो लिखित बयानों में, मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित कर दिया गया) के संबंध में उनके द्वारा स्थापित पूरी रक्षा, जिनसे प्रतिवादियों की बेदखली मांगी गई थी, प्रतिवादी-3, 7 और 8 के लिखित बयान के अनुच्छेद 10 में तथा सभी प्रतिवादियों (जिसमें प्रतिवादी-3, 7 और 8 भी शामिल हैं) के लिखित बयान के अनुच्छेद 5 और 10 में निहित है।

प्रतिवादी-3, 7 और 8 के लिखित बयान का अनुच्छेद 10 इस प्रकार है:

"10. अनुच्छेद संख्या 10 तथ्य के विपरीत और गलत है। अतः इसकी समस्त विषय वस्तु का खंडन किया जाता है। सिख समुदाय 12 वर्षों से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि का मालिक और उसके कब्जे में रहा है, जैसा कि "हिंदू समुदाय" को ज्ञात है, और उनके पास कई ऐतिहासिक दस्तावेज़, समझौता पत्र, तथा अन्य गवाह और प्रमाण हैं, जो उनके पक्ष में यह सिद्ध करते हैं कि विवादित संपत्ति के मालिक, कब्जाधारी और उपभोगकर्ता सिख हैं।

सभी प्रतिवादियों के अनुच्छेद 5 और 10 के लिखित बयान

"5. वादपत्र का अनुच्छेद 5 अस्वीकार किया जाता है। विवादित संपत्ति का किसी भी समय धर्मार्थ विभाग द्वारा कभी प्रबंधन या पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।"

"10. यह कि अनुच्छेद संख्या 10 गलत है और इसलिए अस्वीकार किया जाता है। धर्मार्थ का सिखों के कब्जे में मौजूद कमरों से, जो गुरुद्वारा के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कोई संबंध नहीं था, और न ही उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए सिखों को कमरे दिए। सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्प्रिंग संख्या 2 पर स्थित है, जिसे माचा भवन के नाम से जाना जाता है।वास्तव में, स्प्रिंग संख्या 2 के तीनों ओर 7 गुरुद्वारे थे, जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब के सात बीरे (ग्रंथ) स्थापित थे, प्रत्येक गुरुद्वारे में एक। इसके अलावा, ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारा मट्टन साहिब के तीर्थयात्रियों के उपयोग के लिए 45 कमरे थे। उन

> इमारतों को महाराजा प्रताप सिंह के आदेश पर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि वे बहुत पुरानी थीं और इन स्थानों पर नई इमारत खड़ी करने के उद्देश्य से। लेकिन प्रथम महायुद्ध के कारण सरकार द्वारा प्रस्तावित नया निर्माण कार्य नहीं किया जा सका और गुरुद्वारे के भवन के रूप में केवल वर्तमान सात कमरों की पंक्ति का उपयोग किया गया। इनमें से चार कमरों का वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और शेष तीन कमरों का उपयोग तीर्थयात्रियों के लिए किया जाता है। 1942 में या उसके आसपास गुरुद्वारे के संबंध में सिखों और सरकार के बीच कोई विवाद नहीं था, जैसा कि वादपत्र के इस अनुच्छेद में आरोपित किया गया है, और न ही इस अनुच्छेद में उल्लिखित सरदार कनहैया सिंह तथा अन्य को कभी सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया था, और यदि ऐसा कोई आश्वासन था भी तो सिख समुदाय उनके किसी भी आश्वासन से बाध्य नहीं है''

तथापि, सभी प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में, उन दो कमरों से उनकी बेदखली के विरुद्ध, प्रतिरक्षा के रूप में लिया गया अतिरिक्त निवेदन भी, उसके अनुच्छेद 17(i) में, केवल निम्नलिखित था :

> "(i) यह कि गुरुद्वारा मट्टन साहिब प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी की स्मृति में स्थापित एक ऐतिहासिक सिख तीर्थ है। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने 1657 से पहले इस स्थान का दौरा किया था और तब से यह पवित्र तीर्थ सिखों और सिख इतिहास से जुड़ा रहा है। कश्मीर की विजय के बाद महाराजा रणजीत सिंह के आदेश से गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और एक मुआफी तथा एक जागीर दी गई, जो आज तक जारी है।"

प्रतिवादियों द्वारा अपने लिखित बयानों में प्रस्तुत किया गया प्रतिरक्षा-पक्ष, जैसा कि उनसे प्रतीत होता है, वादियों द्वारा अपने वाद में उनके विरुद्ध प्रस्तुत बेदखली के दावे के विरुद्ध यह नहीं दर्शाता कि वे मारलैंड श्राइन की दक्षिणी धर्मशाला में स्थित दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया

गया था) से बेदखली के लिए उत्तरदायी नहीं थे, इस कारण से कि वे कमरे महाराजा प्रताप सिंह द्वारा, जब वे जम्मू राज्य के संप्रभु शासक थे, अनुदान के रूप में सिख समुदाय को दिए गए थे। यहाँ तक कि यदि प्रतिवादियों के लिखित बयान के उपर्युक्त अनुच्छेदों में निहित कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो यह अनुमान लगाना या कल्पना करना भी असंभव है कि प्रतिवादी दक्षिणी धर्मशाला में स्थित दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया था) से बेदखली के लिए उनके विरुद्ध दायर वाद का विरोध करना चाहते थे, क्योंकि उक्त कमरों का अनुदान महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सिख समुदाय के पक्ष में 'ग्रंथ साहिब' को उन कमरों में आयोजित करने के लिए किया गया था, और इस प्रकार वे जम्मू राज्य के तत्कालीन संप्रभु शासक, महामहिम महाराजा प्रताप सिंह, द्वारा किए गए दो कमरों के अनुदान के स्वामी बन गए थे।

निस्संदेह, विद्वान तृतीय न्यायाधीश (फारूकी, न्यायाधीश) द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि धर्मशाला के दो कमरे महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सिख समुदाय-प्रतिवादियों के पक्ष में प्रदान किए गए थे, एक अन्य विद्वान न्यायाधीश (जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश) के निष्कर्ष से मेल खाता है। परंतु, हमारे विचार में, यह निष्कर्ष पूर्णतः अस्थिर हो जाता है, क्योंकि यह उनके द्वारा प्रतिवादियों के लिए एक बिल्कुल नया मामला बना दिया गया है; ऐसा मामला प्रतिवादियों द्वारा अपनी लिखित बयान में उक्त दो कमरों से बेदखली के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए बचाव के कथनों से किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं है।

इसके अलावा, विद्वान तीसरे न्यायाधीश (फारूकी, न्यायाधीश) इस निष्कर्ष को दर्ज नहीं कर सके कि मार्लैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरे (तीन कमरों में परिवर्तित) सी महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सिख समुदाय-प्रतिवादियों को अनुदान के रूप में दिए गए थे, जब बचाव पक्ष ने अपने लिखित बयानों में प्रतिवादियों से अनुरोध किया था कि सात कमरों वाले धर्मशाला को महाराजा प्रताप सिंह ने सात गुरुद्वारों के बदले में बनवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विद्यमान थे। इससे पहले, दूसरे विद्वान न्यायाधीश

(जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश) द्वारा सहमत होकर इसे अस्वीकार कर दिया गया था। खंड पीठ के अन्य विद्वान न्यायाधीश (अनंत सिंह, न्यायाधीश) ने इस प्रकार कहा:

> "अभिलेख के सबूतों के मूल्यांकन के बाद मैं प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि सात कमरों वाला धर्मशाला महाराजा प्रताप सिंह ने सात गुरुद्वारों के बदले में बनवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले मौजूद थे। इस आशय का अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है। हालांकि, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर सबूत है कि एक धर्मशाला दक्षिणी तरफ मौजूद थी जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और एक नया धर्मशाला बनाया गया था। यह है इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा पेश की गई कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है कि उनके गुरुद्वारे मट्टन तीर्थ के भीतर मौजूद थे..................''

इसके अलावा, जब फारूकी, न्यायाधीश को संदर्भ आदेश के अनुसार, दो विशिष्ट प्रश्नों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी, एक दक्षिणी धर्मशाला में प्रतिकूल कब्जे से दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के लिए शीर्षक के अधिग्रहण से संबंधित था और दूसरा, पहलगाम रोड की ओर खुले स्थान पर प्रतिवादियों द्वारा दीवानों के कब्जे से संबंधित था, अपील पर निर्णय लेने वाले खंड पीठ के दो विद्वान न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के कारण, उनके द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि प्रतिवादियों ने शीर्षक का अधिग्रहण किया था महाराजा प्रताप सिंह द्वारा उनके पक्ष में दिए गए अनुदान के कारण दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) को उनके द्वारा उनकी राय की आवश्यकता वाले संदर्भ की शर्तों से परे बनाया गया माना जाता है।

इसलिए, यह निष्कर्ष कि प्रतिवादियों ने महाराजा प्रताप सिंह द्वारा उनके पक्ष (सिख समुदाय) में दिए गए अनुदान के कारण दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का स्वामित्व हासिल किया, कानून में पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। हम तदनुसार बिंदु-1 का उत्तर देते हैं।

बिंदु - 2:

जब दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा वर्ष 1913 में महाराजा प्रताप सिंह के आदेश पर प्रतिवादियों को सिख समुदाय को 'ग्रंथ साहिब' आयोजित करने के लिए दिया गया था; क्या ऐसा कब्ज़ा अनुज्ञेय कब्ज़े की प्रकृति में था, वह बिंदु है जिस पर यहां हमारे विचार की आवश्यकता है। दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के संबंध में वादी का मामला, जहां से प्रतिवादियों को उनके मुकदमे में बाहर निकालने की मांग की गई है, वह विशेष रूप से उनके वादपत्र में निर्धारित किया गया है जिसे हमने पहले ही बिंदु -1 से निपटने के दौरान संदर्भित किया है और मुकदमे के परीक्षण में उनके साक्ष्य में विशेष रूप से बताया है। वादी का वह मामला संक्षेप में निम्नलिखित है:

यह कि सिखों का एक पुराना गुरुद्वारा एक ऐसे स्थान पर स्थित था जो मार्लैंड श्राइन के परिसर से बहुत दूर था। जब सिक्खों का वह पुराना गुरुद्वारा गिर गया तो सिक्खों को यह पसंद नहीं आया कि वहां रखे उनके 'ग्रंथ साहिब' को हटाकर किसी निजी भवन में रख दिया जाए। परिणामस्वरूप, वर्ष 1913 में, उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह से मार्लैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों को प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संपर्क किया, जो कि सरकारी खर्च पर इसके पुनर्निर्माण के बाद, उनके 'ग्रंथ साहिब' को आयोजित करने के लिए धर्मार्थ विभाग के प्रबंधन में जारी रहे, जब तक कि उनके (सिखों) धर्मशाला का पुनर्निर्माण नहीं हो गया। महाराजा प्रताप सिंह, जिन्होंने सिखों के उक्त अनुरोध को उचित और वास्तविक पाया, ने इसे स्वीकार कर लिया और धर्मशाला विभाग को निर्देश दिया कि वे सिखों को अपने 'ग्रंथ साहिब' को मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों में तब तक आयोजित करने की अनुमति दें, जब तक कि उनके (सिखों के) धर्मशाला का स्वयं या राज्य के खर्च पर पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। तदनुसार, दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों का कब्ज़ा धर्मार्थ विभाग द्वारा सिखों को उनके पवित्र 'ग्रंथ साहिब' आयोजित करने के लिए दिया गया था। धर्मार्थ विभाग सिखों को उनके 'ग्रंथ साहिब' आयोजित करने के लिए दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का

कब्ज़ा देने के समय उल्लेख किया गया था। वह उन हिंदुओं की ओर से दक्षिणी धर्मशाला सहित मार्लैंड श्राइन के मामलों का प्रबंधन कर रहा था, जिनके पास यह मंदिर और धर्मशाला था, क्योंकि धर्मार्थ विभाग स्वयं सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों और धर्मशाला का प्रबंधन संभालने और हिंदुओं के लाभ के लिए इसका प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था; चूंकि मार्तंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला का पुनर्निर्माण हिंदुओं के जीर्ण-शीर्ण धर्मशाला के स्थान पर किया गया था, इसलिए यह हिंदुओं का नहीं रहा, भले ही इस तरह के पुनर्निर्माण को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। वास्तव में, न तो महाराजा और न ही उनकी सरकार ने मार्लैंड श्राइन या धर्मशाला के स्वामित्व अधिकारों को न तो अर्जित किया था और न ही हासिल करने का इरादा था। इस प्रकार, जब सी महाराजा या उनकी सरकार ने मार्लैंड तीर्थ या दक्षिणी पुनर्निर्मित धर्मशाला सहित इसकी संपत्तियों का कोई स्वामित्व अधिकार हासिल नहीं किया था, तो न तो महाराजा और न ही उनका धर्मार्थ विभाग सिखों को अनुदान के माध्यम से धर्मशाला में कोई भी कमरा दे सकता था, जिससे उनमें स्वामित्व अधिकार स्थानांतरित हो जाते। महाराजा के आदेश पर सरकार के धर्मार्थ विभाग द्वारा सिखों को उनके 'ग्रंथ साहिब' आयोजित करने के लिए दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा हिंदुओं की ओर से दिया गया था, जो मार्तंड तीर्थ और उसके धरनास्थलों के मालिक थे और यह प्रकृति में अनुमेय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था।

परीक्षण न्यायाधीश ने मार्तंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के संबंध में प्रतिवादियों के अनुमोदन कब्जे के रूप में वादी के उक्त मामले को इस प्रकार अपना निष्कर्ष दर्ज करके खारिज कर दिया:

> ‘यह उल्लेख भी हो सकता है कि यदि वादी पुराने सिख गुरुद्वारे के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहते हैं, तो वर्तमान धर्मशाला पर प्रतिवादियों के अनुमेय कब्जे के उनके मामले का आधार ही गायब हो जाता है। इसके अलावा अगर यह पाया जाता है कि संगम में ऐसा कोई सिख गुरुद्वारा नहीं था, तो निष्कर्ष अपरिहार्य है कि विभिन्न

अनुदान, और माफ़ियां जो प्रतिवादियों द्वारा साबित की गई हैं, वे केवल मट्टन और मट्टन में स्थित गुरुद्वारे के लिए संदर्भित होंगी क्योंकि यह वादी का मामला नहीं है कि अनुदान को किसी अन्य वादी में किसी अन्य गुरुद्वारे के लिए संदर्भित किया जा सकता है।''

चूंकि परीक्षण न्यायाधीश के उक्त निष्कर्ष की स्थिरता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष वादी पक्ष द्वारा दायर अपील में अनंत सिंह, न्यायाधीश, जो उस खंडपीठ के सदस्य थे, ने मुकदमे में सबूतों पर विचार करने पर उस निष्कर्ष को इस प्रकार उलट दिया,

"दक्षिणी धर्मशाला का पुनर्निर्माण अंततः 1913 में किया गया जैसा कि पक्षों का स्वीकृत मामला है। उपरोक्त दस्तावेज़ (प्रदर्श अ.स. 38/1) से यह प्रतीत होता है कि पुनर्निर्मित धर्मशाला का निर्माण पुराने धर्मशाला पर किया गया था, जिसका निर्माण महाराजा के राज्य के धर्मार्थ विभाग द्वारा किया गया था। धर्मार्थ ऐसा था जैसा कि इसे एक से अधिक बार देखा गया है, केवल हिंदुओं के लिए। अब एक धारणा होगी कि जब धर्मशाला का पुनर्निर्माण राज्य की सहायता से धर्मार्थ द्वारा किया गया था, तो इसका पुनर्निर्माण केवल हिंदुओं के लिए किया गया था। धर्मार्थ महाराजा की निजी संपत्ति नहीं थी, लेकिन महाराजा ने स्पष्ट रूप से इस धर्मशाला का निर्माण अपनी निजी संपत्ति के रूप में नहीं किया था, लेकिन यह धर्मशाला के नियंत्रण और प्रबंधन के तहत हिंदुओं की संपत्ति बनी रही।

"प्रतिवादियों ने न तो अपने किसी भी लिखित बयान में और न ही अपने किसी गवाह के साक्ष्य में यह खुलासा किया है कि वे बलपूर्वक दो कमरों पर कब्जा करने आए थे, या कभी भी हिंदुओं और सिखों के बीच किसी भी विवाद के सामने आने से पहले अपने शत्रुतापूर्ण कब्जे का दावा किया था। इन परिस्थितियों में वादी के मामले पर विश्वास करना मुश्किल है कि प्रतिवादियों को दो कमरों पर अनुमेय कब्जा दिया गया था, क्योंकि महाराजा के आदेश के तहत धर्मार्थ विभाग द्वारा तीन कमरों में परिवर्तित कर दिया गया था। यह सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए

प्रमुख है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा क्योंकि विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने अपने फैसले के पृष्ठ 43 पर कहा है कि वर्तमान धर्मशाला का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह के आदेश के तहत किया गया था जो इमारत के मालिक थे।' इस तरह के निष्कर्ष की गारंटी देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि महाराजा प्रताप सिंह इस इमारत के मालिक इस व्यक्तिगत क्षमता में या राज्य के संप्रभु के रूप में थे। धर्मार्थ विभाग ने महाराजा और उनकी सरकार के कुछ अधिकारियों के आदेश के तहत पुराने धर्मशाला पर शायद सरकारी निधि से भी इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण किया और धर्मार्थ विभाग महाराजा सरकार की एक शाखा थी और धर्मार्थ विभाग केवल हिंदुओं के लिए मौजूद था। इमारत मालिक के रूप में महाराजा की निजी संपत्ति नहीं थी, लेकिन इसका पुनर्निर्माण धर्मार्थ द्वारा हिंदुओं के लाभ के लिए किया गया था, जिनके पास प्राचीन काल से पूरा मंदिर रहा है। महाराजा और उनकी सरकार ने केवल उदारता दिखाते हुए इसके रखरखाव और पुनर्निर्माण में मदद की है। महाराजा ने इसे राज्य के लिए कभी हासिल नहीं किया। अतः वह अपने राज्य की ओर से इसका कोई भी भाग सिक्खों को नहीं दे सका। जाहिर है, इस धर्मशाला के दो कमरों को सिखों को देने का आदेश देकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने महाराज के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर केवल धर्मार्थ के प्रभारी के रूप में कार्य किया था, जो राज्य के संप्रभु थे। *एकमात्र सही निष्कर्ष यह है कि यह धर्मार्थ ही था जिसने हिंदुओं की ओर से तीर्थस्थल के प्रबंधक के रूप में सिखों को दो कमरों का केवल अनुमेय कब्ज़ा दिया था।"*

(हमारे द्वारा जोर दिया गया है)

फिर पुनर्निर्मित धर्मशाला से निपटते हुए, अपील पर निर्णय लेने वाली खंड पीठ के एक अन्य सदस्य, जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश ने अपने अलग फैसले में, अनंत सिंह, न्यायाधीश के फैसले से असहमति नहीं जताई। यह कि मार्लैंड श्राइन के धर्मशाला का निर्माण उसके जीर्ण-शीर्ण पुराने धर्मशाला के स्थान पर किया गया था।

"अभिलेख के सबूतों के मूल्यांकन के बाद मैं प्रतिवादियों के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि सात कमरों वाला धर्मशाला महाराजा प्रताप सिंह ने सात गुरुद्वारों के बदले में बनवाया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले अस्तित्व में थे। अभिलेख पर इस आशय का कोई सबूत नहीं है। हालांकि, अभिलेख में यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि दक्षिणी तरफ एक धर्मशाला मौजूद थी जो जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी जिसे ध्वस्त कर दिया गया था और एक नया धर्मशाला बनाया गया था। इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा पेश की गई कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है कि उनके गुरुद्वारे मट्टन तीर्थ के भीतर मौजूद थे।

(हमारे द्वारा जोर दिया गया)

लेकिन, उनके अनुसार, महाराजा प्रताप सिंह के आदेश पर धर्मार्थ विभाग द्वारा दक्षिणी धर्मशाला में दिए गए दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के कब्जे को माना जाना चाहिए। जम्मू राज्य के संप्रभु शासक के रूप में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा सरकारी संपत्ति देने का आदेश दिया गया, हालाँकि यह महाराजा की निजी संपत्ति नहीं थी।

जैसा कि बिंदु-1 से निपटते समय हमने बताया था, महाराजा प्रताप सिंह द्वारा दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) को सिख समुदाय - प्रतिवादियों के पक्ष में अनुदान का मामला बनाना संभव नहीं था, जब महाराजा प्रताप सिंह द्वारा इस तरह के अनुदान के बारे में उनके लिखित बयानों में प्रतिवादियों के बचाव में कोई दलील नहीं दी गई थी। इसलिए, उक्त संबंध में विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर हो जाता है। इसी कारण से, तीसरे न्यायाधीश, फारूकी, न्यायाधीश के निष्कर्ष को भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि महाराजा प्रताप सिंह ने सिख समुदाय - प्रतिवादियों के पक्ष में दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का अनुदान दिया था, उसे भी बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि बिंदु -1 से निपटने के दौरान हमारे पास है।

जब 1913 में महाराजा प्रताप सिंह के आदेश पर सरकार के धर्मार्थ विभाग द्वारा सिख समुदाय को उनके ग्रंथ साहिब को आयोजित करने के लिए मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के कब्जे की प्रकृति के संबंध में विद्वान परीक्षण न्यायाधीश और विद्वान अपीलीय न्यायाधीशों के निष्कर्षों की जांच उन सबूतों के संदर्भ में की जाती है, जिन पर ऐसे निष्कर्ष आधारित हैं, तो हमारा विचार है कि अनंत सिंह, न्यायाधीश के निष्कर्ष को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि मुकदमे में सबूतों की सही सराहना के आधार पर सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्मार्थ विभाग द्वारा सिख समुदाय को उक्त दो कमरों का कब्ज़ा देने का कार्य किया गया, जिसका प्रतिनिधित्व अब प्रतिवादियों द्वारा किया जाता है। तदनुसार, हम अनंत सिंह, न्यायाधीश के निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं कि वर्ष 1913 में धर्मार्थ विभाग द्वारा सिख समुदाय को दिए गए मार्लैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा केवल अनुमेय कब्ज़ा था और इसके विपरीत अन्य विद्वान परीक्षण और अपीलीय न्यायाधीशों के निष्कर्षों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि बाद वाले या तो किसी प्रासंगिक सबूत पर या अनुमान और अटकलों पर आधारित नहीं हैं।

इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मार्तंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला में सिखों को वर्ष 1913 में दिए गए दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा - प्रतिवादियों को उनके ग्रंथ साहिब को आयोजित करने के लिए स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अनुमेय कब्जे के अलावा और कुछ नहीं था, और उत्तर बिंदु 2 तदनुसार

बिन्दु-3 :

कानून का यह प्रस्ताव कि अनुज्ञेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में नहीं बदला जा सकता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि कब्जे वाले व्यक्ति ने 12 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए वास्तविक मालिकों के ज्ञान के अनुसार संपत्ति पर प्रतिकूल शीर्षक का दावा किया है, तब विवादित नहीं किया जा सकता है, जब *स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम अरवी कुंजू पणिक्कर और अन्य,* एआईआर (1971) एससी 996 (998) में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ ने ऐसा माना है। इसलिए, जब तक

सिख - मुकदमे में प्रतिवादी, जिन्हें वर्ष 1913 में मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के अनुमेय कब्जे में रखा गया था, यह स्थापित करने में सफल नहीं हो सके कि वादी द्वारा मुकदमा शुरू होने से पहले, 12 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए उक्त कमरों के उनके अनुमेय कब्जे के स्वरूप को वास्तविक मालिकों के ज्ञान के प्रतिकूल कब्जे के स्वरूप में बदल दिया गया था, वे अधिग्रहण का दावा नहीं कर सकते हैं। प्रतिकूल कब्जे द्वारा उक्त कमरों का स्वामित्व जब वादी ने अपनी याचिका से अनुरोध किया कि सिख - प्रतिवादी, जो मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) पर अनुज्ञात रूप से कब्जा कर रहे थे, उन्हें वहां से बेदखल करने की आवश्यकता है, तो प्रतिवादियों द्वारा दो लिखित बयान दाखिल करके मुकदमे का विरोध किया गया। प्रारंभिक आपत्तियों के अनुच्छेद 12 में प्रतिवादियों-3, 7 और 8 द्वारा लिए गए प्रतिकूल कब्जे की दलील इस प्रकार है:

> 'विवादित संपत्ति प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से 12 साल से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनिधियों की क्षमता में और उनकी व्यक्तिगत क्षमता में मालिकों के रूप में सिखों के कब्जे में रही है और वे कब्जे में संपत्ति के मालिक हैं।

फिर अनुच्छेद -वार लिखित बयान के अनुच्छेद 10 में, यह इस प्रकार कहा गया है,:

> "10. अनुच्छेद संख्या 10 तथ्यों के विपरीत और गलत है। इसलिए इसकी संपूर्ण विषय वस्तु को अस्वीकार किया जाता है। जैसा कि 'हिंदू समुदाय' को ज्ञात है, सिख समुदाय मालिक रहा है और 12 वर्षों से अधिक समय से मुकदमे की भूमि पर कब्जा कर रखा है और उनके पास उनके पक्ष में कई ऐतिहासिक दस्तावेज, समझौता कार्य और अन्य गवाह और सबूत हैं, जिन्होंने साबित किया है कि विवादित संपत्ति के मालिक, कब्जेदार और सूदखोर सिख हैं।"

सभी प्रतिवादियों द्वारा दायर वाद के लिखित बयान में कहा गया है कि धर्मार्थ विभाग का गुरुद्वारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिखों के कब्जे वाले कमरों से कोई संबंध नहीं था और न ही धर्मार्थ विभाग ने सिखों को किसी भी उद्देश्य के लिए कमरे दिए थे। इस प्रकार, सिखों - प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयानों में हालांकि कहा है कि उनका न केवल दक्षिणी धर्मशाला के

कमरों पर कब्जा था, बल्कि पूरे मंदिर और उसके परिसर पर 12 साल से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा था। उनके लिखित बयानों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उन्होंने धर्मार्थ विभाग को सूचित किया था जो हिंदुओं की ओर से धर्मस्थल और धर्मशाला का प्रबंधन करता था, कि उन्होंने मार्लैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों के अपने अनुमेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में बदल दिया था। मुकदमे में इस आशय का कोई मुद्दा भी नहीं उठाया गया है कि क्या प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे से मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया है।

माना जाता है कि, इस तथ्य को स्थापित करने के लिए सिख-प्रतिवादियों द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक सबूत पेश नहीं किया गया है कि उन्होंने मार्तंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के अपने अनुमेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में बदल दिया था और उन्होंने इस तरह के प्रतिकूल कब्जे से अपना स्वामित्व पूरा कर लिया था। हालाँकि मुकदमे में प्रतिवादियों की ओर से बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई है, लेकिन माना जाता है कि उनमें से किसी ने भी प्रतिकूल कब्जे से प्रतिवादियों द्वारा उक्त दो कमरों के स्वामित्व को सही करने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है।

परीक्षण न्यायाधीश के अनुसार, चूँकि वादी को यह साबित करने में विफल रहे थे कि मार्लैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा सिखों को दिया गया था - प्रतिवादियों और वादी के कुछ गवाहों ने अपने साक्ष्य में कहा था कि प्रतिवादियों ने 1935 में धर्मशाला में उक्त कमरों पर जबरन कब्ज़ा कर लिया था और वादी के कुछ अन्य गवाहों ने कुछ अवसरों पर प्रतिवादियों द्वारा रखे गए कमरों पर जबरन कब्ज़ा करने का उल्लेख किया था। और वह मुख्य दस्तावेज़ जिस पर परीक्षण न्यायाधीश द्वारा भरोसा किया गया था, सन् 1944 ई. में धर्मार्थ विभाग द्वारा, दायर मुकदमा, प्रदर्श अ.स. 27/ब दिनांक 25 कार्तिक 2002, , जो, उस तारीख से 15 दिन पहले जब मुकदमा दायर किया गया था, अर्थात् 25.7.2002 (1944 ई.) यह माना

जाना था कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उक्त दो कमरों पर अपना मालिकाना हक हासिल कर लिया है। प्रतिकूल कब्जे से संबंधित उक्त निष्कर्ष की स्थिरता वादी द्वारा अपील में लगाया गया। जलाल-उद-दीन, और फारूकी, न्यायाधीशो के परीक्षण न्यायाधीश द्वारा बताए गए उन्हीं कारणों से यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे से दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया है। अपीलों पर विचार करने वाले विद्वान न्यायाधीशों में से एक अनंत सिंह, न्यायाधीश ने परीक्षण न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को उलट दिया कि प्रतिवादियों ने दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) के संबंध में प्रतिकूल कब्जे से अपना स्वामित्व पूरा कर लिया था, जिन कारणों के लिए हम वर्तमान स्तिथि पर लौटेंगे।

उनके (अनंत सिंह, न्यायाधीश) के अनुसार, विद्वान परीक्षण न्यायाधीश पर प्रतिकूल कब्जे के सवाल का फैसला करने में सही नहीं थे, क्योंकि वादी ने यह साबित नहीं किया था कि प्रतिवादियों को दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) पर अनुमेय कब्जा दिया गया था, ऐसे में, महाराजा प्रताप सिंह धर्मशाला में कमरों को सिखों के पक्ष में नहीं दे सकते थे, क्योंकि न तो राज्य और न ही उन्होंने इसमें कोई शीर्षक हासिल किया था। दूसरी ओर, उन्होंने यह बताया के हरमार्थ विभाग ने मार्तंड मंदिर और धर्मशाला को अपने कब्जे में ले लिया, तो इसे केवल उन हिंदुओं की ओर से उचित प्रबंधन के उद्देश्य से लिया गया था, जिनके वे थे, अधिग्रहण के माध्यम से नहीं। इसलिए, उनके अनुसार, जब धर्मार्थ विभाग ने, महाराजा के आदेश पर, सिखों-प्रतिवादियों को, हिंदुओं की ओर से, जिनके वे थे, मार्लैंड मंदिर और उसके धर्मशालाओं के प्रबंधकों के रूप में दो कमरे दिए, तो दो कमरों का कब्ज़ा भी दिया जिसमे केवल अनुमोदक कब्जे की विशेषता हो सकती है। वास्तव में, हमने पहले बिंदु-2 से निपटते समय विशेष रूप से इस मामले पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महाराजा प्रताप सिंह के कहने पर धर्मार्थ विभाग द्वारा सिख प्रतिवादियों को उनके ग्रंथ साहिब को आयोजित करने के लिए दक्षिण

धर्मशाला के दो कमरों (तीन कमरों में परिवर्तित) का कब्ज़ा केवल अनुज्ञेय कब्ज़ा था।

अनंत सिंह, न्यायाधीश द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादियों का कब्ज़ा 1913 से अनुज्ञेय कब्जे के साथ शुरू हुआ, यह तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि प्रतिवादी, उसके बाद किसी भी समय, 12 साल की अपेक्षित अवधि के लिए अपने शत्रुतापूर्ण कब्जे का दावा करने में सफल न हो जाए। वास्तव में, इस प्रकार दिए गए तर्क को बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह *स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर मामले* (पूर्व) में इस न्यायालय के फैसले से मेल खाता है। कहा जाता है कि वादी पक्ष के कुछ गवाहों के अनुसार वर्ष 1914 में जबरन कब्ज़ा लिया गया था, जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों द्वारा दो कमरों के संबंध में शत्रुतापूर्ण कब्जे के दावे के वादी पक्ष की ओर से स्वीकारोक्ति के रूप में, उनके द्वारा जबरन कब्जा लेने की तारीख के रूप में संदर्भित वर्ष 1935 को सही नहीं माना गया है, जब दो कमरों का वास्तविक कब्जा वर्ष 1913 में प्रतिवादियों को उनके अनुरोध पर दिया गया था। उन्होंने वादी पक्ष के गवाहों द्वारा की गई तथाकथित स्वीकारोक्ति का भी उल्लेख किया है कि प्रतिवादियों ने कुछ अवधि के दौरान उक्त दो कमरों पर जबरन कब्जा कर लिया था। उनके अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए दो कमरों के प्रतिकूल कब्जे के सवाल पर निर्णय लेने में उस साक्ष्य का कोई महत्व नहीं हो सकता था, ऐसे बयान जो दलीलों पर आधारित नहीं हैं, वे प्रतिवादियों के लिए दो कमरों के प्रतिकूल कब्जे के अपने मामले पर जोर देने के लिए कोई फायदा नहीं उठा सकते थे। मुख्य दस्तावेज़ जिस पर ट्रायल जज द्वारा भरोसा किया गया था वह 1944 ई. प्रदर्श अ.स. में दायर मुक़दमे की शिकायत थी। 27/बी दिनांक 25 कार्तिक 2002, धर्मार्थ विभाग द्वारा, जिसने बाद में प्रदर्श अ.स. 3/2 के अनुसार, महाराजा हरि सिंह के कहने पर वर्ष 1948 में धर्मशाला सहित पूरे मंदिर का कब्जा वादी को वापस सौंप दिया। विद्वान परीक्षण न्यायाधीश के अनुसार, उस वादपत्र में धर्मार्थ विभाग द्वारा दिया गया एक बयान था जो प्रतिवादियों द्वारा दावा किए गए प्रतिकूल कब्जे की स्वीकृति के समान था। यह दिखाने की दृष्टि से कि धर्मार्थ विभाग द्वारा वादपत्र, ईएफ में दिए गए बयान की प्रकृति क्या हो सकती है, इसे

अनंत सिंह, आई.आई. द्वारा इंगित किया गया है। प्रारंभिक आपत्ति पर मुकदमा न्यायाधीश द्वारा वाद-पत्र खारिज कर दिया गया था और धर्मार्थ परिषद वाद-पत्र की अस्वीकृति के खिलाफ अपील में गई थी और अपीलीय न्यायाधीश द्वारा एक संयुक्त आवेदन प्रदर्श अ.स. पर अपील का निपटारा किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा उनके समक्ष 27/बी दायर किया गया। ऐसा कहा गया है कि उस आवेदन से पता चलता है कि धर्मार्थ परिषद-उस मुकदमे में वादी ने मुकदमा वापस ले लिया था और प्रतिवादियों को इस तरह की वापसी पर कोई आपत्ति नहीं थी। विद्वान न्यायाधीश ने पाया है कि वापस लिए गए मुकदमे की याचिका में जो कुछ भी शामिल था, वह ट्रायल जज के लिए यह मानने का आधार नहीं बन सकता था कि धर्मार्थ परिषद ने स्वीकार किया था कि प्रतिवादियों ने मुकदमा दायर करने से 15 दिन पहले अपने कब्जे में दो कमरों पर अपने प्रतिकूल स्वामित्व का दावा किया था। जी इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश ने बताया है कि परीक्षण न्यायाधीश द्वारा जिस वाद पर भरोसा किया गया था, उसमें इस आशय के किसी भी बयान का उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रतिवादियों ने कमरों पर अपने शत्रुतापूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए कोई अतिशयोक्ति की थी और यह केवल उस बात को दर्शाता है जो कमरों के स्थल पर एक एच गुरुद्वारे के प्रस्तावित निर्माण के संबंध में प्रतिवादियों के मन में विचार कर रहा था। यदि ऐसा है, तो यह सोचना मुश्किल है कि परीक्षण न्यायाधीश अपने विचार में सही थे कि दो कमरों के संबंध में प्रतिवादियों की गतिविधियों के बारे में वादी में शामिल धर्मार्थ विभाग का बयान किसी भी तरह से प्रतिवादियों के दावे का समर्थन करता है कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से दो कमरों पर अपना स्वामित्व पूरा कर लिया है, जैसा कि अनंत सिंह, न्यायाधीश ने सही तर्क दिया था।.

निष्कर्ष में, विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादियों द्वारा उनके कब्जे में दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों के संबंध में प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न पर इस प्रकार कहा है:

> "अब इस मद पर अपने निष्कर्षों को सारांशित करने के लिए मैं फिर से कह सकता हूं कि दक्षिणी धर्मशाला शुरू से ही हिंदुओं की संपत्ति थी।

इसे हिंदुओं के पुराने धर्मशाला पर बनाया गया था। यदि महाराजा प्रताप सिंह ने इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण अपनी सरकार द्वारा करवाया था, तो उन्होंने इसे धर्मार्थ विभाग के धन से किया था, जो उनकी सरकार का एक अलग विंग था। धर्मार्थ विभाग हिंदुओं के लिए था। इसमें केवल तीर्थ का नियंत्रण और प्रबंधन था। यदि धर्मशाला महाराजा सरकार की संपत्ति थी, उन्होंने 1948 में इसे पूरे मंदिर के साथ हिंदुओं को वापस दे दिया....."

उक्त कारण, जो माननीय न्यायाधीश (अनंत सिंह, न्यायाधीश) द्वारा दिए गए थे, जिन्होंने मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) के संबंध में परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दिए गए प्रतिकूल कब्जे के निष्कर्ष को पलट दिया था, हमारे विचार में सुविचारित और ठोस हैं तथा उन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। चूँकि फारूकी, न्यायाधीश का निष्कर्ष, जो दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) के संबंध में प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के प्रश्न पर जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश के निष्कर्ष से मेल खाता है, परीक्षण न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादियों के पक्ष में धर्मशाला के दो कमरों के प्रतिकूल कब्जे के संबंध में दिए गए उन्हीं कारणों पर आधारित है, इसलिए वही कारण, जिनके आधार पर अनंत सिंह, न्यायाधीश ने परीक्षण न्यायाधीश द्वारा दिए गए दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) के प्रतिकूल है।

इस प्रकार, फारूकी, न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादियों ने मारलैंड श्राइन की दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, पूर्णतः अस्थिर सिद्ध होता है, और हम बिंदु-3 का उत्तर उसी के अनुसार देते हैं।

बिंदु-4:

हम यहाँ फ़ारूकी न्यायाधीश के निष्कर्ष की स्थिरता से संबंधित हैं, जो जलाल-उद-दीन, न्यायाधीश के इस निष्कर्ष से मेल खाता है कि प्रतिवादियों ने तीन अवसरों—अर्थात् बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही—पर पहलगाम रोड की ओर मारलैंड दरगाह के

खुले स्थान में अपने दीवान आयोजित करने के लिए उपभोगाधिकार प्राप्त कर लिए थे। संबंधित खुला स्थान झरनों के उत्तर में, पहलगाम रोड की ओर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 19 कनाल और 6 मरला है। वादियों ने अपने मुकदमे में सिखों—प्रतिवादियों— को अपने दीवान या सभा आयोजित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रयास किया, इस आधार पर कि यह खुला स्थान मारलैंड दरगाह का अभिन्न हिस्सा था जो हिंदुओं का था और यह स्थान प्राचीन काल से हिंदुओं के कब्जे में था तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता रहा था। हिंदुओं द्वारा दायर वाद में प्रतिवादियों को खुले स्थान का उपयोग करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोकने के लिए किया गया दावा, प्रतिवादियों द्वारा अपने लिखित बयान के अनुच्छेद 9 में प्रस्तुत किए गए तर्क के आधार पर विरोध किया गया, जो इस प्रकार था:

> ''9.......खसरा संख्या 1424/4 के अंतर्गत आने वाली 19 कनाल और 6 मरला भूमि अनादि काल से सिखों के विशेष कब्जे में है, जो गुरुद्वारा श्री मट्टन साहिब का अभिन्न हिस्सा है, जहाँ वे सिख समुदाय की संगतें, बैठकें और दीवान आयोजित करने करते हैं ....''

दुर्भाग्यवश प्रतिवादियों के लिए, उनके लिखित बयान में किया गया यह दावा कि खसरा संख्या 1424/4 के अंतर्गत आने वाली भूमि, जिसका क्षेत्रफल 19 कनाल 6 मरला है, गुरुद्वारा श्री मट्टन साहिब के हिस्से के रूप में सिखों के विशेष कब्जे में है, इसे न केवल परीक्षण न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, बल्कि उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों द्वारा भी, जिन्होंने परीक्षण न्यायाधीश के निर्णय से उत्पन्न अपीलों पर विचार किया। वास्तव में सभी विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में दिया गया स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादियों का यह मामला कि वे मरलैंड दरगाह और सर्वे संख्या 1424/4 के अंतर्गत आने वाली भूमि पर अनादिकाल से गुरुद्वारा श्री मट्टन साहिब के हिस्से के रूप में कब्जे में थे, पूरी तरह से असत्य पाया गया है। अनंत सिंह, न्यायाधीश, जो उस खंड पिठ के सदस्य थे जिसने अपील की सुनवाई की थी, उन्होंने उक्त खुले स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कहा है:

> "यह खुला स्थान मंदिर में स्थित सभी संरचनाओं, इमारतों और स्रोतों के बीच में स्थित है। ये सभी एक सतत समग्र इकाई हैं, जो चारदीवारी और

इमारतों से घिरी हुई हैं, तीन ओर से और पूर्व दिशा में ऊँची भूमि से। सामान्यतः इस खुले स्थान का कब्जा उन भौतिक संरचनाओं, इमारतों और स्रोतों के कब्जे के साथ ही माना जाएगा, जिनके बीच यह स्थित है। यह खुला स्थान का यह बड़ा हिस्सा पश्चिम में धर्मशाला भवन के उत्तर में, पूर्व में उत्तर मंदिरों के एक कक्ष के पास, और दक्षिण में तीन झरनों के बीच स्थित है। मंदिरों तक पहुँचने का मार्ग इस खुले स्थान से होकर गुजरता है। धर्मशाला और उत्तर-पश्चिम में स्थित अन्य भवनों तक पहुँच भी केवल इस खुले स्थान के पार से ही संभव है। यह देखा गया है कि मंदिर परिसर के भीतर स्थित अन्य सभी वस्तुएँ हिंदुओं के कब्जे में रही हैं। मंदिरों में से एक प्राचीन पाया गया है। झरने भी प्राचीन पाए गए हैं। यह भी पाया गया है कि वे अनादि काल से हिंदुओं के कब्जे में रहे हैं। यह पाया गया है कि हिंदू लोग पूरे वर्ष विभिन्न अवसरों पर झरनों के पास मुंडन, श्राद्ध आदि जैसे अनेक संस्कार करते रहे हैं। यह खुला स्थान ही एकमात्र जगह है जहाँ हिंदू अपने संस्कारों को करने के लिए एकत्रित होते थे .....

पूरे मंदिर परिसर सहित वह खाली स्थान, जैसा कि पहले देखा गया है, राजस्व अभिलेखों में हिंदुओं के कब्जे में दर्ज किया गया है, और इस स्थान को 'बंजर क़दीम' के रूप में वर्णित किया गया है। प्रतिवादियों ने इस खुले स्थान के संबंध में भी लंबे समय से वादियों के कब्जे को स्वीकार किया है, लेकिन अब उन्होंने इस पर केवल संयुक्त कब्जे का दावा किया है, जिसमें हिंदुओं के साथ उनका साझा कब्जा बताया गया है, और उन्होंने अपने मूल विशेष कब्जे के दावे को छोड़ दिया है। उनके संयुक्त कब्जे का स्वरूप परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष बहस के दौरान इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि वे हर वर्ष तीन निर्दिष्ट अवसरों पर लंबे समय से 'दीवान' आयोजित करने करते रहे हैं।

तत्पश्चात, उपरोक्त स्थान के संबंध में वादियों और प्रतिवादियों के साक्ष्यों का गहन विचार करने पर, वही विद्वान न्यायाधीश इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैं:

"यह भूमि प्राचीन काल से ही वादियों के मंदिर का अभिन्न हिस्सा रही है। वे निस्संदेह पूरे संपत्ति के स्वामी हैं, जिसमें विवादित खुला स्थान भी शामिल है।"

इसके पश्चात, प्रतिवादियों के उस दावे से निपटते हुए कि वे प्रथा के आधार पर तीन विशिष्ट अवसरों पर दीवान रखते आए हैं, माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि किसी अन्य की भूमि के उपयोग का प्रथागत अधिकार तब तक कायम नहीं रखा जा सकता जब तक कि ऐसा अधिकार दावा करने वाला पक्ष यह सिद्ध न कर दे कि यह अधिकार प्राचीन, शांतिपूर्ण, युक्तिसंगत और विशिष्ट है, और ऐसा अधिकार अधिकारस्वरूप तथा निरंतर बिना किसी हस्तक्षेप के प्रयोग किया जाता रहा है, इस न्यायालय के निर्णय *राजा ब्रजा सुंदर देब और अन्य बनाम मणि बेहरा और अन्य,* एआईआर (1951) एससी 247 पर निर्भर करते हुए कहा। उनका मत था कि प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण दीवान आयोजित करने के उक्त दावे को टिकाऊ नहीं माना जा सकता, और जिन प्रतिवादियों ने वास्तव में खुले स्थान पर स्वामित्व अधिकार का दावा किया था, उन्हें यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि वे पलटकर उस भूमि पर दीवान आयोजित करने का अधिकार, उपभोगाधिकार या दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर, उस संबंध में अपने लिखित कथन में कोई वैकल्पिक निवेदन किए बिना, दावा करें। इस प्रकार, उन्होंने खुले स्थान में दीवान आयोजित करने के प्रतिवादियों के अधिकार के दावे को अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश अल-उद-दीन, जो खंडपीठ के एक अन्य सदस्य थे, ने यह मत व्यक्त किया कि प्रतिवादी उस खुले स्थान का उपयोग करने के अधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में अपना उपभोगाधिकार स्थापित कर लिया था। इस कारण, प्रतिवादियों द्वारा उपभोगाधिकार के माध्यम से दीवान आयोजित करने के लिए उस स्थान के उपयोग का अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न, इस पर निर्णय हेतु तीसरे न्यायाधीश को संदर्भित किया गया। तीसरे न्यायाधीश, फ़ारूक़ी न्यायाधीश, ने यद्यपि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि

अधिकार अभिलेख और जमाबंदी में प्रविष्टि जब "ऐज़ कबज़ाहल हिन्दन्स", " के रूप में थी, तो इसका अर्थ था कि खुली जगह का कब्ज़ा हिंदू धर्म के अनुयायियों का था, उन्होंने यह मत लिया कि संपत्ति को अधिकार अभिलेख और जमाबंदी में बंजर क़दीम' के रूप में दर्ज किए जाने का अर्थ यह था कि उस संपत्ति पर खेती नहीं की जाती थी, और इसलिए ऐसी प्रविष्टियों को सनातनी हिंदुओं के लिए या हिंदुओं के मारलैंड तीर्थ के लिए विशेष रूप से समर्पित भूमि के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। हम पाते हैं कि फ़ारूक़ी, न्यायाधीश द्वारा 'बंजर क़दीम' प्रविष्टि के आधार पर इस मामले में लिया गया यह दृष्टिकोण उचित नहीं था, जब उन्होंने स्वयं अधिकार अभिलेख और जमाबंदी की प्रविष्टियों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाती हैं कि उपर्युक्त स्थान, तीर्थ की अन्य भूमि के साथ, हिंदुओं के विशेष कब्ज़े में दिखाया गया था। अतः, प्रतिवादियों द्वारा खुले स्थान पर उपभोगाधिकार के रूप में अधिकार के अधिग्रहण के मामले में अनंत सिंह, न्यायाधीश का विपरीत दृष्टिकोण, हमारे अनुसार, इस विषय पर फ़ारूक़ी, न्यायाधीश द्वारा व्यक्त मत पर प्रबल होता है। हमारे विचार में माननीय न्यायाधीश फ़ारूक़ी, फिर से गलत थे जब उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों ने लिखित बयान के अनुच्छेद 9 का संदर्भ देकर दीवान आयोजित करने के अधिकार को उपभोगाधिकार के रूप में प्राप्त करने की दलील ली थी, जो इस प्रकार था:

"खसरा संख्या 1424/4 द्वारा आच्छादित भूमि, जिसका माप 19 कनाल 6 मरला है, सिखों के अनन्य कब्जे में प्राचीन काल से है, जो गुरुद्वारा श्री मट्टन साहिब का एक हिस्सा है, जहाँ वे सिख समुदाय की सभाएँ, बैठकें और दीवान आयोजित करते थे।"

ऊपर लिखित बयान के अनुच्छेद 9 में लिया गया निवेदन, जैसा कि उसके साधारण पढ़ने से स्पष्ट होता है, यह है कि सिखों ने खसरा संख्या 1424/4 से आच्छादित भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि वह भूमि प्राचीन काल से उनके कब्जे में थी और गुरुद्वारा श्री मट्टन साहिब का हिस्सा

थी, न कि यह कि उन्होंने उस भूमि पर दीवान या सभा करने का कोई उपभोग अधिकार प्राप्त किया था, जो भूमि हिंदुओं की थी।

अतः, माननीय न्यायाधीश का यह दृष्टिकोण कि लिखित बयान के अनुच्छेद 9 में प्रतिवादियों द्वारा किया गया दावा उपभोगाधिकार के अधिकार के दावे के रूप में माना जा सकता है, पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। यदि ऐसा है, तो फ़ारूकी, न्यायाधीश जो अपीलों का निर्णय करने वाले माननीय तृतीय न्यायाधीश थे, यह निष्कर्ष किया कि सिखों ने खुले स्थान पर धार्मिक समारोहों या दीवान आयोजित करने के संबंध में तीन विशिष्ट अवसरों, अर्थात् बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही, पर अपना उपभोगाधिकार स्थापित कर लिया था, पूर्णतः अस्थिर हो जाता है। हम बिंदु-4 का उत्तर तदनुसार देते हैं।

बिंदु-5:

यहाँ मुद्दा यह है कि क्या सिखों को मार्तंड मंदिर के दक्षिणी धर्मशाला में स्थित उन दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ वे अपना ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, क्योंकि फ़ारूकी, न्यायाधीश के इस निष्कर्ष के अनुसार कि सिख—प्रतिवादियों ने या तो महाराजा प्रताप सिंह द्वारा उनके पक्ष में किए गए अनुदान के माध्यम से उन दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित हो गए) पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, या फिर प्रतिकूल कब्जे के द्वारा अपना अधिकार पूर्ण कर लिया था, अस्थिर पाया गया है।

न्याय के हित में, हमारे मत में, सिखों—प्रतिवादियों—को मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के उन दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं) से बेदखल करने का आदेश देना उचित नहीं है, जहाँ वे अपना ग्रंथ साहिब रख रहे हैं, इस मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और विशेष रूप से वादियों द्वारा प्रस्तुत उस मामले को ध्यान में रखते हुए जिसमें उक्त दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित कर दिए गए हैं) का सिखों—प्रतिवादियों—को अनुमतिपूर्ण कब्जा दिए जाने की बात कही गई है, जिसे हम सत्य मानते हैं। वादपत्र के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि धर्मार्थ विभाग ने

सिखों को अस्थायी रूप से ग्रंथ साहिब दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए थे) में, जो मार्तंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के थे, आयोजित करने की अनुमति दी थी, जब तक कि उनकी (सिखों की) गिरी हुई धर्मशाला, जो मारलैंड तीर्थ से दूर थी, का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता ताकि वे वहाँ अपना 'ग्रंथ साहिब' रख सकें। उसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि धर्मार्थ विभाग और माननीय मंत्री के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया कि दोनों कमरों को खाली कराया जाएगा और ग्रंथ साहिब को नई धर्मशाला में रखा जाएगा और इन दो कमरों का उपयोग ग्रंथ साहिब को आयोजित करने के लिए तब तक किया जाएगा जब तक नई धर्मशाला का निर्माण सरकारी खर्च पर नहीं हो जाता। यह भी उसमें उल्लेख किया गया है कि समझौता पत्र 4 असुज 1992 को सिखों और धर्मार्थ विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा वज़ीर वज़ारत अनंतनाग और माननीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था, जिसमें उक्त कमरों के संबंध में धर्मार्थ विभाग और सिखों - प्रतिवादियों के बीच विवाद का समाधान किया गया। यह स्वीकार किया गया है कि अभी तक कोई नई धर्मशाला, जिसे या तो सिखों द्वारा या सरकार द्वारा बनाया जाना था, नहीं बनाई गई है ताकि सिख - प्रतिवादी अपने गुरु ग्रंथ साहिब को मारलैंड मंदिर की दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) से स्थानांतरित कर सकें और उन कमरों को खाली कर सकें। जब दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) का कब्जा सिखों - प्रतिवादियों को उनके गुरु ग्रंथ साहिब आयोजित करने के लिए महाराजा प्रताप सिंह के निर्देश पर धर्मार्थ विभाग द्वारा दिया गया था, तब सरकार का धर्मार्थ विभाग, जो मारलैंड मंदिर की दक्षिणी धर्मशाला के प्रबंधन में था, ने अपने दो कमरे सिखों को उनके गुरु ग्रंथ साहिब आयोजित करने के लिए दिए थे, जब तक कि एक नई धर्मशाला सिखों द्वारा स्वयं या उनके लिए सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती, ताकि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को स्थानांतरित किया जा सके। हिंदू, जो वादी हैं, हमारे विचार में, धर्मार्थ विभाग द्वारा प्रबंधक के रूप में मारलैंड मंदिर और उसके धर्मशालाओं के संबंध में उनके लिए की गई कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति से बच नहीं सकते। इसके अलावा, प्रतिवादियों की ओर से यह भी महसूस किया गया है कि सिखों की ओर से मारलैंड मंदिर और उसके

परिसर के संबंध में उनके द्वारा किया गया स्वामित्व का दावा पूरी तरह से अनुचित था, जैसा कि उनके लिखित प्रस्तुतियों के अनुच्छेद 39 और 40 में कही गई बातों से स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार हैं:

> "39. इस माननीय न्यायालय में अपील दायर किए जाने के बाद माननीय तृतीय न्यायाधीश के निर्णय के पश्चात से ही पक्षकारों ने द्वैधपीठ द्वारा निर्धारित स्थिति को स्वीकार कर लिया है और तब से कोई उल्लेखनीय विवाद नहीं रहा है, बल्कि तब से शांति और सद्भाव बना हुआ है। प्रतिवादियों ने इस माननीय न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की है, यद्यपि अंतिम निर्णय आंशिक रूप से उनके विरुद्ध है। उन्होंने अपील इस उद्देश्य से दायर नहीं की कि क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बना रहे। "
>
> "40. अपीलकर्ताओं ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है और इस माननीय न्यायालय को यह भी सूचित किया है कि उन्हें प्रतिवादियों द्वारा तीन कमरों के कब्जे के निरंतर बने रहने तथा तीन त्योहारों: दशमी, छट्टीपातशाही और बैसाखी के उत्सव मनाए जाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं है, जो इस अपील का विषय है"

अतः, हमारे विचार में, न्याय के हित में यह नहीं होगा कि प्रतिवादियों को उक्त दो कमरों (जो अब सी तीन कमरों में परिवर्तित हो चुके हैं) से, जो मारलैंड श्राइन की दक्षिणी धर्मशाला में स्थित हैं, बाहर निकाला जाए, जैसा कि वादियों ने वाद में माँग की है। तथापि, उक्त दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित हो चुके हैं) पर उनका कब्जा जारी रखने का अधिकार, जहाँ उन्होंने अपना ग्रंथ साहिब रखा है, को अनुमतिपूर्ण कब्जा माना जाना चाहिए, और कोई भी ऐसा कार्य जो सिखों – प्रतिवादियों द्वारा इन कमरों पर उनके अनुमतिपूर्ण कब्जे का लाभ उठाकर किया जाए, जिससे मंदिर में पूजाओं के संपादन या झरनों अथवा मंदिर के खुले स्थानों पर हिंदुओं द्वारा धार्मिक समारोहों के आयोजन में बाधा उत्पन्न हो सकती हो, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि

इससे हिंदुओं—वादी पक्ष—को प्रतिवादियों को दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए हैं) से बेदखल करने के लिए उपयुक्त विधिक कार्यवाही का सहारा लेकर कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होता है। हम विचाराधीन बिंदु का उत्तर उसी अनुसार देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 142(1) का सहारा लेते हुए, जो इस न्यायालय को किसी भी मामले या कारण में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है।

बिंदु-6:

यहाँ मुद्दा सिखों के अधिकारों से संबंधित है—प्रतिवादियों का वर्ष के तीन विशिष्ट अवसरों, अर्थात बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही के समय पहलगाम रोड की ओर स्थित मारलैंड श्राइन के खुले स्थान में दीवान आयोजित करने का अधिकार। निस्संदेह, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रतिवादी खुले स्थान में ऐसे दीवान आयोजित करने के लिए उपभोगाधिकार स्थापित करने में असफल रहे हैं। फिर भी, जब वादियों ने प्रतिवादियों—सिखों को मारलैंड श्राइन की दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरे (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए हैं) अपने ग्रंथ साहिब आयोजित करने के लिए प्रदान किए हैं और जब आवश्यकता के कारण सिख—प्रतिवादी उन दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए हैं) के निकट किसी सुविधाजनक स्थान पर दीवान आयोजित करने के लिए बाध्य हैं, तो न्याय के हित में सिखों को रोकना उचित नहीं होगा -उपर्युक्त खुली जगह में मारलैंड श्राइन के पहलगाम रोड की ओर, तीन अवसरों पर दीवान आयोजित करने की अनुमति दी गई थी, जब ऐसी दीवान आयोजित करने की अनुमति जलाल-उद-दीन न्यायाधीश और फ़ारूकी, न्यायाधीश द्वारा अपीलों का निर्णय करते समय दी गई, भले ही हम इसके लिए दिए गए कारणों से सहमत नहीं हैं। तथापि, इस प्रकार दी गई अनुमति समाप्त हो जाएगी जब प्रतिवादियों का मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (जो तीन कमरों में परिवर्तित किए गए) पर अनुमेय कब्जा समाप्त हो जाएगा। मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला में दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया) का उदार कब्जा समाप्त हो जाता है। न्याय के हित में स्वयं यह स्पष्ट किया जाता है कि सिख—प्रतिवादी—जब भी वर्ष में उन तीन अवसरों में से किसी पर,

जिनका उल्लेख उक्त माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया गया है, पहलगाम रोड की ओर स्थित मारलैंड श्राइन के खुले स्थान में दीवान आयोजित करने का निर्णय लें, तो ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे दीवानों में भाग लेने के इच्छुक लोग सीधे पहलगाम रोड से संबंधित खुले स्थान तक पहुँचें और अन्य मार्तंड श्राइन परिसर या उन झरनों को पार न करें, जहाँ हिंदू अपने पूजा-पाठ या धार्मिक समारोह या अनुष्ठान कर रहे होंगे। यदि उक्त दीवान का आयोजन इस प्रकार करने का प्रयास किया जाता है या किया जाता है कि लोगों को मारलैंड श्राइन परिसर के अन्य को पार करते हुए खुले स्थान में दीवान के लिए एकत्र होने की अनुमति दी जाए, या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जो हिंदुओं को—जो वादी हैं—प्रतिवादियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कारण प्रदान करें ताकि उन्हें मारलैंड श्राइन के खुले स्थान में, पहलगाम रोड की ओर, दीवान या सभाएँ आयोजित करने से रोका जा सके, जैसा कि माननीय न्यायाधीश जलाल-उद-दीन और न्यायाधीश फ़ारूकी, द्वारा वर्तमान अपील में अपने निर्णयों में अनुमति दी गई है, तो हम इस विचाराधीन बिंदु का उत्तर उसी के अनुसार देते हैं, संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हमारे समक्ष प्रस्तुत वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए, क्योंकि इसकी असाधारण प्रकृति है।

हमारे द्वारा इस अपील में हमारे विचारार्थ उत्पन्न प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों के समग्र प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह अपील निरस्त किए जाने योग्य है, इस शर्त के अधीन कि प्रतिवादियों पर मारलैंड तीर्थ के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) से बेदखली की देयता होगी, यदि वे अपने अनुमतिपूर्ण कब्जे का दुरुपयोग करते हैं जिसके अंतर्गत उन्हें उन कमरों में बने रहने की अनुमति दी गई है, तथा प्रतिवादियों की यह देयता भी होगी कि उन्हें मारलैंड तीर्थ के पहलगाम रोड की ओर स्थित खुले स्थान का उपयोग वर्ष में तीन अवसरों पर दीवान आयोजित करने के लिए रोका जाए, यदि वे या उनके लोग अब प्रदान की गई इस अनुमति का दुरुपयोग करते हुए ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं जो हिंदुओं को

उनकी पूजा करने या अपने ही मारलैंड तीर्थ और उसमें स्थित स्रोतों के परिसर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बाधा या असुविधा उत्पन्न करें।

परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है। तथापि, मारलैंड श्राइन के दक्षिणी धर्मशाला के दो कमरों (जिन्हें तीन कमरों में परिवर्तित किया गया है) पर सिखों (प्रतिवादियों) का अनुमत कब्जा जारी रहना, तथा वर्ष में तीन अवसरों—बैसाखी, दसवीं और छठी पादशाही—पर पहलगाम रोड की ओर स्थित मारलैंड श्राइन के खुले स्थान का उनका उपयोग, इस अपील में हमारे द्वारा विचारित बिंदुओं पर हमारे उत्तर दर्ज करते समय लगाए गए शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

इस अपील में विवाद की प्रकृति को देखते हुए, व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

टी.डब्ल्यू. अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद (तलत परवीन) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।